

# **VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH**

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 6.6.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

**LIBERALISATION, PRIVATISATION**

**AND**

**GLOBALISATION: AN APPRAISAL**

## **BACKGROUND**

The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s. We know that for implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises etc. When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutions. When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports. 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन से वित्तीय संकट की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि विभिन्न नीतियों और इसके सामान्य प्रशासन को लागू करने के लिए, सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे कराधान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने आदि से धन उत्पन्न करती है। जब आय से अधिक खर्च होता है, तो सरकार बैंकों से घाटे का वित्तपोषण करने के लिए उधार लेती है और लोगों से भी देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से। जब हम पेट्रोलियम जैसे सामान का आयात करते हैं, तो हम डॉलर में भुगतान करते हैं जो हम अपने निर्यात से कमाते हैं।

Development policies required that even though the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. The continued spending on development programmes of the government did not generate additional revenue. Moreover, the government was not able to generate sufficiently from internal sources such as taxation. When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defence, there was a need to utilise the rest of its revenue in a highly efficient manner. The income from public sector undertakings was also not very high to meet the growing expenditure. At times, our foreign exchange, borrowed from other countries and international financial institutions, was spent on meeting consumption needs. Neither was an attempt made to reduce such profligate spending nor sufficient attention was given to boost exports to pay for

the growing imports. विकास नीतियों की आवश्यकता थी कि भले ही राजस्व बहुत कम था, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को अपने राजस्व का निरीक्षण करना पड़ा। सरकार के विकास कार्यक्रमों पर निरंतर खर्च से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ। इसके अलावा, सरकार कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त रूप से उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। जब सरकार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों पर खर्च कर रही थी जो सामाजिक क्षेत्र और रक्षा जैसे तत्काल रिटर्न प्रदान नहीं करते हैं, तो अपने बाकी राजस्व का अत्यधिक कुशल तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आय भी बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए बहुत अधिक नहीं थी। कई बार, हमारा विदेशी मुद्रा, अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लिया जाता था, उपभोग की जरूरतों को पूरा करने पर खर्च किया जाता था। न तो इस तरह के विपुल खर्च को कम करने का प्रयास किया गया और न ही बढ़ते आयात के भुगतान के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया।

In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. Prices of many essential goods rose sharply. Imports grew at a very high rate without matching growth of exports. As pointed out earlier, foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than two weeks. There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lenders. Also no country or international funder was willing to lend to India. 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, सरकारी व्यय इतने बड़े मार्जिन से अपने राजस्व से अधिक होने लगे कि उधार के माध्यम से खर्च को पूरा करना अनिश्चित हो गया। कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं। निर्यात की वृद्धि के बिना आयात बहुत अधिक दर से हुआ। जैसा कि पहले बताया गया था, विदेशी मुद्रा भंडार एक स्तर तक गिर गया जो दो सप्ताह से अधिक के लिए वित्त आयात के लिए पर्याप्त नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं को दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। इसके अलावा कोई भी देश या अंतरराष्ट्रीय फंड भारत को कर्ज देने को तैयार नहीं था।

India approached the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), popularly known as World Bank and the International Monetary Fund (IMF), and received \$7 billion as loan to manage the crisis. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalise and open up the economy by removing restrictions on the private sector,

reduce the role of the government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries. भारत ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नाम से जाना जाता है, और इस संकट को प्रबंधित करने के लिए 7 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया। ऋण का लाभ उठाने के लिए, इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उम्मीद की कि भारत निजी क्षेत्र पर प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को मुक्त करेगा और कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को कम करेगा और भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाएगा।

India agreed to the conditionalities of World Bank and IMF and announced the New Economic Policy (NEP). The NEP consisted of wide ranging economic reforms. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. This set of policies can broadly be classified into two groups: the stabilisation measures and the structural reform measures. Stabilisation measures are short-term measures, intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control. In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. On the other hand, structural reform policies are long-term measures, aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. The government initiated a variety of policies which fall under three heads भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तों पर सहमति व्यक्त की और नई आर्थिक नीति (एनईपी) की घोषणा की। एनईपी में व्यापक आर्थिक सुधार शामिल थे। नीतियों का जोर अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और फर्मों के प्रवेश और विकास की बाधाओं को दूर करने की ओर था। नीतियों के इस समूह को मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय। स्थिरीकरण उपाय अल्पकालिक उपाय हैं, जिसका उद्देश्य उन कुछ कमजोरियों को दूर करना है जो भुगतान संतुलन में विकसित हुई हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, संरचनात्मक सुधार नीतियां दीर्घकालिक उपाय हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कठोरता को हटाकर अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करना और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। सरकार ने कई तरह की नीतियां शुरू कीं जो तीन प्रमुखों के अंतर्गत आती हैं